

1. **पृष्ठभूमि:**— जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनियमितता सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन का असर पिछले कुछ वर्षों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा है। वर्षापात में कमी आयी है तथा मौनसून का व्यवहार अत्यंत ही असामान्य हो गया है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के अनुसार फसल चक्र तथा कृषि तकनीक में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुये किसानों को सक्षम बनाने के लिए जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की स्वीकृति दी गयी है।
2. **परियोजना लागत एवं अवधि:**— यह योजना वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित की जायेगी। इस परियोजना का कुल परियोजना लागत 6065.50 लाख (साठ करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार) रू० है।
3. **परियोजना क्षेत्र:**— परियोजना के दो प्रमुख अवयव हैं। पहला अवयव किसानों के खेत में उपलब्ध जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक के पत्यक्षण से संबंधित है। योजना के इस अवयव का कार्यान्वयन मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया तथा नालन्दा जिलों में किया जायेगा। प्रत्येक जिला से पाँच गाँवों को जलवायु के अनुकूल मॉडल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जायेगा। इस प्रकार यह परियोजना आठ जिलों के 40 गाँवों में कार्यान्वित किये जायेंगे। परियोजना का दूसरा अवयव अनुसंधान से संबंधित है जो परियोजना कार्यान्वयन के लिए चिन्हित संस्थानों के स्तर पर कार्यान्वित किया जायेगा।
4. **परियोजना के प्रमुख अवयव:**— इस योजना के अधीन जलवायु के अनुकूल फसल तथा फसल प्रभेद के व्यवहार, लेजर लैण्ड लेवलिंग, हैप्पी सीडर जीरो टिलेज, धान की सीधी बुवाई, रेज-बेड प्लाटिंग, संरक्षित खेती, फसल अवशेष प्रबंधन/मल्टिपिंग तकनीक को प्रदर्शित किया जायेगा जिसे किसान देखकर सीख सकेंगे। मौसम से अनुकूलता से संबंधित अवयवों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है,
 - मौसम का पूर्वानुमान, आवश्यकता के अनुसार बीज तथा कृषि वानिकी के हस्तक्षेप प्रमुख रूप से कार्यान्वित किये जायेंगे।
 - परियोजना के अधीन सिंचाई जल के महत्तम उपयोग के लिए धान की सीधी बुआई, धान में वैकल्पिक जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, भूमि का समतलीकरण, मेड़ पर फसलों की बुआई की तकनीक प्रमुख रूप से कार्यान्वित किये जायेंगे।
 - परियोजना के अधीन कार्बन संरक्षण के लिए ज़िरो टिलेज, फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक प्रदर्शित किये जायेंगे।
 - परियोजना के अधीन पोषक तत्व प्रबंधन से संबंधित मक्का एवं गेहूँ के लिए न्यूट्रीयेन्ट एक्सपर्ट, ग्रीन सीकर का प्रयोग एवं फसल चक्र में दलहनी फसलों के उपयोग की तकनीक प्रदर्शित किये जायेंगे।
5. **परियोजना का कार्यान्वयन:**— इस योजना का कार्यान्वयन बोरलॉग इंस्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र, पटना के वैज्ञानिकों के द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक अनुभव का लाभ राज्य के किसानों को होगा। कृषि विभाग के कर्मी आवश्यकतानुसार परियोजना कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे।